Chapter 5

bihar board class 8th history notes शिल्प एवं उद्योग

शिल्प एवं उद्योग

पाठ का सारांश–भारत वैसे तो मूलत: एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं दद्योगके क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी रहा है। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजों के शासन से पहले काफी विकसित अवस्था में थे। यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मुगलों के शासनकाल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में सामान निर्यात होता था। विशेषकर ढाके की मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छींट, अहमदाबाद की धोतियाँ और दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारी वाले कपड़े एवं कुछ अन्य सूती वस्त्र का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाध्द में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी थी।

मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनैतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों तथा यूरोपीय शासकों के आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुँचाया । कई क्षेत्रीय शासकों ने, अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों पर अधिक कर लगा दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आयी। इससे उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे-बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और भड़ौच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा, कर्नाटक में बंगलौर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै तथा आंध्रप्रदेश में विशाखापत्तनम और मछलीपट्टम । कश्मीर ऊनी वस्त्र
के लिए प्रसिद्ध था।

यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में अक्षम था। अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंगलैंड ने सन् 1720 में कैलिको अधिनियम बनाया और भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया। इसके बावजूद यूरोप के बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग बहुत अधिक थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, जिसका विदशों में निर्यात होता था।
इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे है से सजावटी डिजाइने बनायी जाती थी। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई केन्द्र थे। यूरोप के बड़े घरों तथा यहाँ के रजवाड़े परिवार के लोगों द्वारा इन महंगे कपड़ों की खरीदारी की जाती थी।

भारत के वस्त्र उद्योग एवं उनकी यूरोप में विक्री खत्म या कम करने के लिए सन् 1813 ई. में इंगलैंड सरकार ने 'मुक्त व्यापार की नीति अपनाई । इस एकतरफा नीति से इंग्लैंड को भारत में अपना माल बेचने पर कोई कर नहीं लगता था। पर, भारतीय माल पर इंग्लैंड में आयात कर
लगने से यहाँ के वह वहाँ महंगे विकते थे जिससे उनकी बिक्री बहुत कम हो गई। परिणामस्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूत कातने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी।

https://www.evidyarthi.in/

अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय शिल्प एवं उद्योगों का धीरे-धीरे पतन होने लगा।
अंग्रेजी शासन से पहले कृषि, हस्त शिल्प एवं कुटीर उद्योग का बहुत बढ़िया संतुलन था, लेकिन कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश ने इस संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब शहर छोड़कर गाँवों में लौट खेती करने को बाध्य हो गये।
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ भारतीय मशीनी उद्योग की तरफ आकर्षित हुए। सबसे पहले उन्होंने वस्त्र उद्योग की स्थापना की क्योंकि इसके कारखाने को खोलने के लिए कम पूँजी की आवश्यकता थी। उसके बाद जूट एवं कोयला खान उद्योगों की भी स्थापना की गयी। सन्
1880 ई. तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी।
सन् 1855 ई. में बंगाल के रिशरा में पहली जूट मिल स्थापित की गयी। 1906 में कोयलाखान उद्योग की शुरुआत की गयी । बीसवीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था।
सन् 1907 में जमशेद जी टाटा ने बिहार (झारखंड) के साकची नामक स्थान पर यटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) की स्थापना की। आज यह स्थान जमशेदपुर नाम से जाना जाता है। यहाँ स्टील का उत्पादन होने लगा।
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में कागज, चीनी, आटा आदि की मिलें भी खोली गयी । यहाँ नमक, अभ्रक और शोरे जैसे खनिज उद्योगों की भी स्थापना हुई। नील, चाय और कॉफी जैसे बगान उद्योगों का भी विकास हुआ। भारत का औद्योगिक विकास सन् 1914 के बाद ही हो सका। 1945 ई. तक इंग्लैंड दो विश्वयुद्धों के बीच युद्ध की सामग्री बनाने व उनको नियत स्थानों पर पहुंचाने में ही व्यस्त रहा।
इन दो विश्वयुद्धों के बीच भारतीय उद्योगों, विशेषकर कपड़ा उद्योग को काफी बढ़ावा मिला और इनका तीव्र विकास हुआ। अब भारत में दो वर्ग प्रमुखता से दिखने लगे—एक तो औद्योगिक पूँजीपति वर्ग दूसरे मजदूर वर्ग । मजदूरों का जीवन अत्यन्त कठिन था और आमदनी बेहद कम ।
उस पर से उन्हें 15-16 घंटों से लेकर 18 घंटों तक काम करना पड़ता था। वे कारखानों के बगल में झुग्गी-झोपड़ियों में रहते थे जहाँ सफाई एवं पानी तक की सुविधा नहीं थी।
अपनी दयनीय दशा के खिलाफ मजदूरों ने आंदोलन किया जिसका अंग्रेजों ने साथ दिया ।
उनके काम के घंटे और न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गयी। अंग्रेजों ने ऐसा भारतीय उद्योगपतियों को मुश्किल में डालने के लिए किया था। ताकि उत्पादन-दर बढ़ जाए उनके माल का और वे यूरोप के माल से प्रतियोगिता न कर सकें।
फिर तो अन्य सुविधाओं के लिए भारतीय मजदूरों ने आन्दोलनों की राह पकड़ ली। आगे चलकर यही मजदूर भारत स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने में सहायक रहे।
स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार भारत के शिल्प एवं उद्योग के विकास के लिए भी सतत् प्रयत्नशील रही। एक 'औद्योगिक नीति' बनायी गयी जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए।

https://www.evidyarthi.in/